भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3562

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)

भुवनेश्वर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रोज़गार की स्थिति

3562. श्रीमती अपराजिता सारंगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून 2026 तक भुवनेश्वर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) खोरधा जिले में असंगठित और प्रवासी निर्माण श्रमिकों की संरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का उद्योग और शिक्षा के बीच रोजगार-क्षमता के अंतर को पाटने के लिए भुवनेश्वर में एक नया राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) केंद्र या महाकौशल केन्द्र स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, ओडिशा राज्य (भुवनेश्वर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित) में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 17.2% से घटकर वर्ष 2025 में 10.6% हो गई है।

इसके अलावा, ओडिशा राज्य (भुवनेश्वर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के खोरधा जिले सहित) में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने देने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022 में 55.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 61.3% हो गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में (जिसमें भुवनेश्वर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का खोरधा जिला शामिल है) विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) भी चला रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना**,** सरकारी सहायता तक पहुँच का विस्तार करना और एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल में कुल 8.9 करोड़ सूक्ष्म**,** लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं जिसमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) भी शामिल है जिससे देशभर में 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई**)** ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए **'**फ्यूचर स्किल्स प्राइम**'** कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके अलावा, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99**,**446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। सरकार ने ओडिशा राज्य में 32 केंद्रों सहित देश भर में 407 मॉडल करियर केंद्रों को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" लॉन्च किया, जिसमें एक पोर्टल पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाएं एकीकृत हैं और इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और उनके द्वारा अब तक प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनते हैं।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15) योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है ताकि ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ और उन तक पहुँच प्रदान की जा सके, जिनमें प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवानिधि), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत-रोजगार एवं अजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) एवं प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), आदि शामिल है।

उपरोक्त के अलावा, ई-श्रम नौकरी के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) और आवसान एवं शहरी कार्य मंत्रालय के कन्वर्जेंस पोर्टल के साथ जुड़ा है, जो ई-श्रम कार्डधारकों को अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

*****